nwda.gov.in

जारी रहेगा जल जीवन मिशन, रखरखाव पर जोर

2028

तक शत-प्रतिशत कवरेज के लिए मिशन को मिला विस्तार

- **राज्यों को मरम्मत और रखरखाव के लिए करने होंगे एमओयू**

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : पानी के बिना काम नहीं चलेगा और यह अनवरत मिलना भी चाहिए। जल जीवन मिशन शत-प्रतिशत ग्रामीण घरों में यह आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही इसकी निरंतरता की भी चिंता करेगा। 2019 में शुरू किए गए इस मिशन को ना केवल 2028 तक विस्तार मिल गया है, बल्कि केंद्र सरकार ने इसके तहत गांवों में पानी की आपूर्ति के बुनियादी ढांचे की स्थायी व्यवस्था करने का भी फैसला किया है।

राज्यों को इसके लिए केंद्र सरकार के साथ नए सिरे से एमओयू पर हस्ताक्षर करने होंगे। इस पहल के जरिये केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन को लेकर उठ रहे इन सवालों के जवाब दे दिए हैं कि नल से जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के बाद इसकी निरंतरता की चिंता कौन करेगा यानी पाइप के जरिये जलापूर्ति में रखरखाव और मरम्मत का खर्च कौन उठाएगा।

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में जल जीवन मिशन का महत्व रेखांकित करते हुए कहा कि इसके तहत अब तक 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से पानी की आपूर्ति की जा चुकी है। यह कुल ग्रामीण आबादी का लगभग 80 प्रतिशत है। 15 अगस्त, 2019 को जब पीएम ने इस मिशन की शुरुआत की थी तब केवल तीन करोड़ ग्रामीण घरों में टैप से पानी की आपूर्ति की सुविधा थी, लेकिन पांच साल में अब ऐसे घरों की संख्या पांच गुना बढ़ चुकी है। विश्व बैंक और डब्ल्यूएचओ सरीखे संगठनों ने भी इस मिशन को ग्रामीण जीवन में बुनियादी बदलाव लाने वाला बताया है। जलशक्ति मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इस मिशन के तहत सौ प्रतिशत कवरेज का लक्ष्य इस साल के अंत तक हासिल हो जाने की संभावना है। इसके बाद मिशन का मुख्य फोकस ओएंडएम यानी संचालन तथा रखरखाव पर होगा। इस मिशन में दो करोड़ रोजगार सृजित होने की भी संभावना है।

अगले वित्तीय वर्ष में इस मिशन में 67 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। मौजूदा वित्तीय वर्ष में भी 70 हजार करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया था, लेकिन चुनावी वर्ष होने और मिशन के भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति के कारण लगभग 23 हजार करोड़ रुपये ही खर्च किए जा सके। मूल योजना के तहत दिसंबर, 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में नल से जल की आपूर्ति सुनिश्चित हो जानी चाहिए थी, लेकिन कोविड महामारी और रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण पाइप आदि के आयात में दिक्कतों के चलते ऐसा नहीं हो सका।